राज्यों को केन्द्रीय योजना सहायता देने के लिए मानदंड

3134. **श्री मनोहर क्रान्त ध्यानी:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों को योजना के अंतर्गत केन्द्रीय योजना सहायता प्रदान करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या योजना आयोग उत्तरांचल/उत्तराखंड के लिए विशेष आवेदन करता है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंवटन मानदंडों के अनुसार किया गया है; और

(घ) यदि हां,तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तरांचल को कितना आबंटन किया गया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलघ): (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड विवरण में दिया गया है (**नीचे देखिए**)।

(ख) योजना आयोग उत्तराखण्ड के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय योजना सहायता समग्र रूप से भी राज्य योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई जाती है और इसके एक भाग को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड के लिए मुहैया कराया जाना है।

(ग) विवरण (नीचे देखिए) में दिया गया फार्मूला समग्र तौर पर वैयक्तिक राज्यों की विशेष केन्द्रीय योजना सहायता के आवंटन के लिए हैं न कि एक राज्य के भीतर उत्तराखण्ड जैसे क्षेत्रों के लिए यद्यपि, देश में विनिर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता का पारस्परिक वितरण जनसंख्या और प्रदेश के क्षेत्र के आधार पर इन घटकों में से प्रत्येक को समान महत्व प्रदान करते हुए किया जाता है। उत्तर प्रदेश को परवर्ती मानदण्ड के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन निम्नलिखित है:

करोड़ रुपये

वर्ष	एससीए का आवंटन
1994-95	197.06
1995-96	225.00
1996-97	225.00

विवरण

राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्ड

श्री प्रणव मुखर्जी, उपसभाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में केन्द्रीय वित्त मंत्री और योजना आयोग के एक सदस्य सहित एक समिति राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूला की पुनरीक्षा हेतु गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों पर 23 और 24 दिसंबर, 1991 को हुई राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की बैठक में विचार किया गया था और राज्यों को केन्द्रीय सहायता के वितरण हेतु निम्नलिखित फार्मूला निर्धारित किया गया था।

I. कुल केन्द्रीय सहायता में से, विदेशी सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए उपेक्षित निधियां अलग रखी जाए, जैसाकि वर्तमान रूप में किया जा रहा है।

II. शेष में से, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के लिए सम्यक राशि मुहैया कराई जाए अर्थात

क. पहाड़ी क्षेत्र
ख. जनजाति क्षेत्र
ग. सीमा क्षेत्र
घ. एन ई सी
ङ अन्य कार्यक्रम

III. शेष में से 30% को विशेष श्रेणी राज्यों को दिया जाए।

IV. निम्नलिखित फार्मूले के अनुसार शेष को गैर विशेष श्रेणी राज्यों में वितरित किया जाए।

मानदण्ड	भार-%
1. जनसंख्या (19971)	60
2. प्रति व्यक्ति आय	25
(क) "विचलन" पद्धति राष्ट्रीय औसत से नीचे प्रति व्यक्ति एसडीपी वाले राज्यों को कवर करना	20

(ख) दूरी पद्धति सभी राज्यों को कवर करना।	5
3.निष्पादन	7.5
क. टैक्स प्रयास	2.5
ख. वित्त प्रबंध	2.0
ग. राष्ट्रीय उद्देश्य	3.0
1. जनसंख्या नियंत्रण	1.0
2. महिला निरक्षरता को दूर करना	1.0
3. विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करना	0.5
4. भूमि सुधार में सफलता	0.5
4. विशेष समस्याएं	7.5

Diversion of plan allocations into non-plan expenditure

3135. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the plan allocation were diverted to non-plan expenditure by the State Government during the Eighth Five Year Plan;

(b) if so, the names of such States and details of funds involved;

(c) whether Government have taken or proposed to take any steps to control non-plan expenditure of States; and

(d) if so, the details thereof alongwith the details of achievements made in this regard.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) The Central Government is not aware of any diversion of plan funds for non-plan except that the Special Category States have been allowed to utilise upto 20% of the net normal Central assistance for meeting their non-plan gap. Further, Assam and Jammu & Kashmir States were allowed to utilise upto 30% of the net normal central assistance for non-plan gap during 1992-93. States have been advised time to time, to contain the non-plan revenue expenditure.

Special programme for the development of North Eastern region

3136. DR. B.B DUTTA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to undertake special programme for economic development of the north-east region;

(b) if so, the details of the plans worked out in this direction; and

(c) whether Government propose to implement these plans?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (c) The then Prime Minister issued a Statement on 27th October, 1996, at Guwahati comprising programmes/schemes/projects for the economic development of the seven North-Eastern States. The details of his Statement were placed in the House in reply to Unstarred Question No. 1292 on 4th December, 1996. The programmes/schemes/projects envisaged in the Statement are being implemented.

Differences in per capita income

3137. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the per capita income during 1995-96 at constant price was Rs. 2573 and the current prices was Rs. 9321;

(b) whether it is also a fact that a wide differences in per capita income at current prices vis-a-vis constant prices is on account of three-times increase in the prices of essential commodities;

(c) if so, the details of the per-capita income for 1995-96 at 1951, 1961, 1971, 1981 and 1991 price level; and

(d) the details of the per capita incomes (1995-96) at constant prices as well as current prices and the major causes for wide disparities at State level?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND